THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS : (SHRI K. C. PANT. (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have reported that a case has been registered and that the owner of the Press and four employees have been arrested.

Communal Tension Prevailing in Assam

6137. SHRI MADHURYYA HALDAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :-

(a) whether the attention of Government has been drawn to the communal tension prevailing in Assam, which was sparked at the Lumding Junction of N. F. Railway, where a particular community people were manhandled by another section ; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by Government to control the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). A petty incident that took place between some persons belonging to two linguistic groups at Lumding Railway Station on 27th April, 1971 led to incidents of violence on the following few days in the valley districts of Assam. According to information received from the Government of Assam, altogether 166 cases were registered in connection with these incidents and 356 persons had been arrested in those cases till 1 June, 1971. The State Government also initiated action under the law against the newspapers which had given undue publicity to the Lumding incident. To enable the police to take effective action several non-cognisable offences under the IPC, which are usually committed in the course of disturbances, were made cognisable for a period of three months

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा सरकारी रिपोर्टों का अनुवाद

6138. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने कौन-कौन से सरकारी विभागों की रिपोर्टों का अनुवाद किया ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971 को हुई थी। इसका कार्य असांविधिक कार्यविधि साहित्य का अनुवाद करना है। ब्यूरो ने अभी तक किसी रिपोर्ट का अनुवाद कार्य हाथ में नहीं लिया है। रिपोर्टों का अनुवाद करने की जिम्मेदारी सामान्यत: संबंधित मंत्रालयों / विभागों की होती है।

राज्यों में निचली अदालतों में अंग्रेजी का प्रयोग

6139. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान की प्रतियां न मिलने के कारण राज्यों में निचली अदालतों को अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखना पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह निर्णय करना कि निचली अदालतों में किस भाषा का प्रयोग किया जाय, राज्य सरकार का काम है। क्षेत्रीय भाषाओं में संविधान के अधिकृत रूपान्तर न मिलने के कारण राज्यों की निचली अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओ के प्रयोग में कोई अड़चन आई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। फिर भी संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं (कश्मीरी, सिन्धी तथा संस्कृत को छोड़ कर) में आधुनिकतम अनुवाद का कार्य राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा शुरू किया गया है।

Demand for no change in Personal Law of Muslims

6140. SHRI N. K. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :-

(a) whether the All India Muslim Political Convention has demanded that the Personal Law of Muslims should not be interfered with ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?